Vice-President is releasing a book on Rajya Sabha. Then we will have it on Monday or some other day that is convenient. We will let the Members know. We will get it announced.

RE: REPEATED INTRUSION BY CHINESE FORCES INTO INDIAN TERRITORY FROM THE NORTH

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली): उपसभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की ओर दिलाना चाहता हूं। पिछली 4 फरवरी से 18 फरवरी के बीच चीन के सशस्त्र गार्ड ने भारतीय सीमा में 6 बार प्रवेश किया और यह प्रवेश उन्होंने कोई थोड़े गज या मीटर तक नहीं किया बल्कि 5/6 किलोमीटर तक भारतीय सीमा में उन्होंने प्रवेश किया।

महोदया, यह बहुत ही गंभीर बात है और सुरक्षा की दृष्टि से तो यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो वहां पर ट्रेक जंक्शन है उस सीमा पर पहले कभी इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई थी और आम तौर पर वहां शांति रहती है। वहां पर इन 14 दिन के अंदर 6 बार चीनी सुरक्षा गार्ड भारी असले से लैस होकर, बहुत ज्यादा हथियार लेकर, भारतीय सीमा में प्रवेश करते हैं और वह भी 5/6 किलोमीटर तक अंदर चले आए और फिर वापस चले गए। फिर आएं, फिर वापस चले जाएं, ऐसी स्थिति वहां पर हुई है।

महोदया, ईस्टर्न और वेस्टर्न सैक्टर में तो इस प्रकार की घटनाएं थोड़ी बहुत होती रही हैं, लेकिन इस सैक्टर के अंदर यह घटनाएं पहली बार हुई हैं। इसको ज्यादा गंभीरता से लिया जाना चाहिए था, परन्तु हमारा रिएक्शन क्या हुआ? पहली बात तो यह हुई कि जब भी वे आते हैं 6 किलोमीटर अंदर तक, तो हम लोग सफेद झंडा लेकर वहां खड़े हो जाते हैं और सफेद झंडा दिखाकर उनके पास यह कहते हुए चले जाते हैं कि हमारे ऊपर गोली न चलाना। उनके पास ऐसे जाते है और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। रिक्वेस्ट सुनने के बाद वे वहां से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन फिर आ जाते हैं और फिर चले जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, उपसभापति महोदया, अपने विदेश मंत्री जी से कि यह कौनसा तरीका है? .....(**व्यवधान**)....यह क्या हो रहा है, मंत्री ही आपस में बोले चले जा रहे हैं तो बाकी का क्या है।

उपसभापति: आप तो मेरे लिए कहिए। मैं सुन रही हूं।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : मुझे समझ में नहीं आ रहा, बार बार मंत्री उठ रहे हैं। ....(**व्यवधान**)....

उपसभापति: मैं सुन रही हूं। मैंने सुना कि उनके गार्ड आते हैं, बार बार भारतीय सीमा में घुसते हैं और घुसपैठ करके चले जाते हैं। वह एरिया बहुत शांतिपूर्ण है। वहां भी गड़बड़ हो रही है। आप बोलिए। मैं सुन रही हूं।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे रिऐक्शन का यही तरीका है? हम इतने साफ्ट क्यों हैं? हमें उनके द्वारा हमारी सीमा के भीतर प्रवेश करते ही उनके विरुद्ध कुछ कार्यवाही करनी चाहिए लेकिन इसके बजाय हम सफेद झंडा लेकर वहां खड़े हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि शू-आऊट नहीं होना चाहिए और उनसे रिक्वैस्ट करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और वे वापस चले जाते हैं।

महोदया, ईस्टर्न और वैस्टर्न सैक्टर में जो कुछ घटनाएं हुई हैं वे दुर्भाग्यपूर्ण हैं। हमारा चीन के साथ समझौता हुआ। आपने उसके बारे में यहां आकर बड़े जोर से घोषणा की, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में उसका जिक्र आया, आपकी पार्टी के लोग भी इस बारे में बोले। उन्होंने कहा कि बड़ा भारी ऐतिहासिक समझौता हुआ है कि हम भी पीछे हट जाएं और वे भी पीछे हट जाएं, ताकि इस तरह की घटना न हो। वास्तव में यदि देखा जाए तो चीन हमारी सीमा में ही पीछे हटा और हम अपनी सीमा में और पीछे हट गए। पहले जहां एक साल में इस तरह की एक घटना होती थी, वहां अब 14 दिन में 6 बार इस तरह की घुसपैठ हुई है। क्या यह हमारे समझौते का परिणाम है? समझौता तो हमने इसलिए किया था कि ताकि सेनाओं को आपस में संघर्ष न करना पड़े और इस तरह की घटना न हो परन्तु ये तो 14 दिनों में 6 बार हमारी सीमा के अंदर आ गए और इसके बाद आपका रियेक्शन क्या है? मैंने कल खुद अखबार में देखा कि गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय इस बारे में विचार कर रहे हैं कि इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करें। यह 4 फरवरी और 18 फरवरी के बीच की घटनाओं के बारे में प्रोटेस्ट करने की बात अब सोची जा रही है। अब 10 दिन के बाद यह सोचा जा रहा है कि कोई प्रोटेस्ट किया जाए या न किया जाए।

महोदया, मैं समझता हूं कि यह जो स्थिति है, इसी के कारण वे बार-बार आते हैं। इसी कारण वे हिमाचल प्रदेश में कई मील तक अंदर आ जाते हैं। इसीलिए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। पहली बात तो यह है कि हमें उनको सख्त वार्निंग देनी चाहिए कि आज आप आ गए, ठीक है लेकिन इसके बाद अगर आएंगे तो सीधे-सीधे उनके ऊपर हमला करना चाहिए, शूट-आऊट करना चाहिए। हमारी सीमा में कोई अनधिकृत रूप से प्रवेश करता चला जाएगा तो हम सफेद झंडा लेकर बैठे रहेंगे? यह आपकी सॉफ्टनैस उनको ऐनकरेज करती है बार-बार आने के लिए। वे बॉयनाक्यूलर लेकर आते हैं, उससे वे वहां के नक्शे उतारते हैं, फोटोग्राफ लेते हैं और हथियार लेकर आते हैं। आपने अभी तक प्रोटेस्ट नहीं किया है, आपने प्रोटेस्ट करने की जरूरत तक नहीं समझी है। यह स्थिति बन रही है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से 3 बातें पूछना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि अभी तक विरोध क्यों नहीं किया गया? दूसरी बात यह है कि हर बार आप उनके खिलाफ कोई ऐक्शन लेने के बजाय सफेद झंडा लहराकर उनसे रिक्वैस्ट क्यों करते हैं? तीसरी बात यह है कि चीन के साथ सीधी बातचीत क्यों नहीं की जाती, आप अपने वहां के काऊंटरपार्ट के साथ सीधी बातचीत क्यों नहीं करते कि यह समझौता होने के बाद भी इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है?

महोदया, यह सुरक्षा की दृष्टि से और हमारे स्वाभिमान की दृष्टि से बहुत गंभीर समस्या है और मैं चाहूंगा कि विदेश मंत्री इस पर जरूर कमेंट करें।

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI I.K. GUJRAL): Madam, normally one does not respond to this, but let me respond to this because....

श्री विष्णुकांत शास्त्री (उत्तर प्रदेश): मैं इसी पर कुछ बोलना चाहता हूं। आप इस पर आगे बोल सकते हैं।

SHRI I.K. GUJRAL: I am conscious of the fact that it is a very serious matter that my friend has raised. I will pass on his sentiments to my colleague, the Defence Minister and the Government will come forward with a statement next week.

उपसभापति: अब इस पर कहने को क्या रह गया है? स्टेटमेंट आ रहा है ना।

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी (उत्तर प्रदेश): अच्छा हो ये बोल लें। ये जो मुद्दे उठा रहे हैं, स्टेटमेंट में उनका भी जवाब आ जाएगा।

श्री विष्णुकांत शास्त्री: महोदया, मेरे मित्र मल्होत्रा जी ने बहुत गंभीर समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया है। मुझे उसमें एक बात जोड़नी है कि मेरी जानकारी के अनुसार पिछले वर्ष भी ऐसे उल्लंघन हुए थे। यह पहली बार नहीं है। मल्होत्रा जी का कहना है कि संभवतः पहली बार मध्य क्षेत्र में ऐसे उल्लंघन हुए हैं, यह बात ठीक नहीं है। मेरी सूचना के अनुसार पिछले वर्ष भी ऐसे उल्लंघन इस क्षेत्र में हुए थे।

महोदया, यह संयोग की बात है कि स्टेट्समैन ने इस समाचार को प्रकाशित किया। स्टेटमैन अगर इस समाचार को प्रकाशित नहीं करता तो मैं नहीं जानता कि हमारे माननीय विदेश मंत्री इस बारे में प्रतिवाद करते या नहीं करते क्योंकि अभी तक प्रतिवाद नहीं हुआ। परसों पहली बार जब स्टेट्समैन ने इस समाचार को प्रकाशित किया, तब तक प्रतिवाद नहीं हुआ था। आज स्टेटमैन में समाचार छपा है कि विदेश मंत्रालय उपक्रम कर रहा है, सोच-विचार कर रहा है कि वह किस तरह से प्रतिवाद करे। महोदया, आज 26 फरवरी है, मुझे नहीं मालूम कि हमारे विदेश मंत्री 4 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक क्यों प्रतिवाद नहीं कर सके?

क्या इसकी सूचना हमारे विदेश मंत्रालय को नहीं थी? क्या यह चाहते नहीं थे कि विदेश मंत्री यह बात संसद में रखते। कल माननीय प्रधान मंत्री जी ने बारीपाड़ा में जो अग्निकांड हुआ उसके बारे में स्वयं प्रेरित होकर एक वक्तव्य दिया। आज माननीय विदेश मंत्री ने स्वयं प्रेरित होकर एक वक्तव्य दिया। क्या यह घटना उन घटनाओं से कम महत्वपूर्ण है? क्या हमारा देश कोई अनाथालय है कि जो विदेशी सैनिक हैं छह-छह बार आ जाए। चीनी सैनिक क्यों आ रहे हैं? उनकी नीयत क्या है? मुझे यह बताया गया है कि वे वहां कोई सुरक्षात्मक निर्माण करना चाहते हैं। वे वहां पर ऐसी स्थायी स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं जिससे कि हमारी फौजें वहां अग्रसर न हो सकें। मैं केवल माननीय विदेश मंत्री जी से ही नहीं, देश के माननीय रक्षा मंत्री जी से भी आश्वासन चाहता हूं कि हमारी फौजें वहां सतर्क हैं और हमारी फौजें वहां किसी भी आक्रमण का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि कितने और उल्लंघन होने के बाद वे अपने जवानों को यह निर्देश देंगे कि उसका योग्य प्रतिउत्तर दिया जाए। क्या वह उल्लंघन पर उल्लंघन

करते चले जाएंगे और हम लोग यहां बैठकर केवल प्रस्ताव पास करेंगे और सोचते रहेंगे कि हम चीन की सरकार के पास प्रतिवाद करें तो किस रूप में करें जिससे उनके कोमल हृदय को चोट नहीं लगे। मैं जानना चाहता हूं कि हमारे विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री अपनी उदारता का परिचय किस सीमा तक देना चाहते हैं।

श्री नरेन्द्र मोहन: एक छोटी सी बात मैं पूछना चाहता हूं....(व्यवधान)

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am sorry, I am not allowing. Please help me to run the House. When the Defence Minister comes here, then you may put your important questions. Please listen to me. I know that you are a very knowledgeable person but my problem is that the names of Members who sought permission from the Chairman are listed before me. Will I be doing justice if I allow the names that are not listed against those who have the permission? You yourself decide. The House should decide as to what I should do. The Members have taken permission from the hon. Chairman. If I do not permit them, where will they go? I am just requesting every Member to abide by the list. I know, you have something to contribute which is a good thing. The Foreign Minister, Mr. Gujral has indicated that the Defence Minister would be coming to the House and I am sure of it. When he comes, I will allow you as the first person to speak on it. This is my assurance.

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश): हमारा भी नाम था।

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is not on my list. (*Interruptions*)

नाम था नहीं, आपने मांगा था। मगर वह पहले से नहीं था। जो पहले से है वही है मेरे पास।

श्री ईश दत्त यादव: जब शास्त्री जी ने अपना नाम दिया तभी मेरा नाम था।

उपसभापति: नहीं था। You do not join hands like this. For a special mention, the procedure is that each Member should give a separate notice. Two people cannot sign on the same. You should give a separate notice. (*Interruptions*) I understand.

आप भी बोल लीजिएगा जब डिस्कशन होगा। यह कॉलिंग अटेंशन थोड़ी है कि इसमें 5-6 नाम होंगे। मगर लिस्ट में नहीं लिखा है।

RE. CRISIS IN I.D.P.L.

श्री जलालुद्दीन अंसारी (बिहार): मैडम, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या की ओर आपके माध्यम से ओर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 25 फरवरी से आई०डी०पी०एल० के कर्मचारी दिल्ली में जंतर मंतर रोड पर धरना दे रहे हैं। आई०डी०पी०एल० की पांच इकाईयां पूरे देश में हैं — ऋषिकेश, गुड़गांवा, हैदराबाद, मद्रास और मुजफ्फरपुर। भारत के प्रथम प्रधान मंत्री पं० जवाहर लाल नेहरू ने देश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आई०डी०पी०एल० की स्थापना की थी। यह हम सभी जानते है कि आई०डी०पी०एल० जीवन रक्षक दवाएं बनाती है। अभी हाल के ही दिनों में ऐसी बीमारियां आ गई तो उसकी दवाईयां नहीं मिलती थी, बाहर से मंगानी पड़ती थी। प्लेग हो गया था गुजरात में। हमारे देश में अभी भी कालाअजर होता है, मलेरिया होता है। अपने देश की आवश्यकता के अनुरूप आई०डी०पी०एल० की स्थापना की गई है लेकिन दुख की बात है कि इसका रिवाइवल पैकेज भी बनाया गया। आई०डी०बी०आई० के अधीन इसको चलाने की कोशिश भी की गई लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस पुनरुद्धार योजना को चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल भी कभी नहीं दिया गया। न इसके लिए कोई बजट में खास व्यवस्था की गई और न वित्तीय संस्थानों से मदद ही दी गई । आज हालत यह हो गई है कि पांचों इकाइयां करीब-करीब बंद पड़ी हुई है, अक्टूबर 1996 से बंद हैं। सरकार ने क्या किया कि मद्रास और मुजफ्फरपुर यूनिट को सबसीडियरी घोषित कर दिया। इसके पीछे सरकार की नीयत यह है कि आई०डी०पी०एल० को सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान से निजी क्षेत्र में दे दिया जाए या संयुक्त क्षेत्र में दे दिया जाए या विदेशी कंपनियों के हवाले कर दिया जाए। यह है सरकार की नीयत और इस तरह से ये जो लाइफ सेविंग ड्रग्ज़ हैं, जीवन-रक्षक दवाएं हैं, जिनकी हमारे देश की जनता को आज भी आवश्यकता है, उसको चलाने में सरकार सही रुख नहीं अपना रही है। हमारे माननीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र्स मिनिस्टर भी यहां मौजूद हैं। इनसे भी बार-बार हम लोग निवेदन कर रहे हैं, पिछली सरकार से निवेदन करते रहे हैं लेकिन सरकार